

विचार बिन्दु

यदि चिड़ियाँ एकता कर लें, तो शेर की खाल खींच सकती हैं। –शेख सादी

क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं?

जब से इंडियन एक्सप्रेस में चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विभिन्न निर्णयों पर असहमति संबंधित प्रकरण सामने आए हैं, तब से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में निरंतर विरोध चल रहे हैं। यह लगभग स्पष्ट हो चुका है की चुनाव आयोग के नाम पर कई निर्णय अकेले ज्ञानेश कुमार ही कर रहे थे जबकि आयोग के निर्णय या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए थे। यहां तक कि “स्पेशल इंटीसिव रिवीजन” या एस आईआर कराने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भी आयोग में तीनों आयुक्तों के नाम द्वारा नहीं लिया गया था। स्वयं चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस विज्ञापन से ही स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु न तो आयोग की मीटिंग हुई, न एजेंडा बनाया गया न ही मिनिट्स जारी किए गए। एस आईआर संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित परिपत्रों को भी दो आयुक्तों की लिखित असहमति के बावजूद ज्ञानेश कुमार ने अपनी इच्छा अनुसार लागू किया। इस मनमानी का परिणाम यह हुआ कि देश में लगभग 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए, फॉर्म 6 में बदलाव कर दिया गया, नाम जोड़ने हटाने का अधिकार ई आर ओ से लेकर आयोग के मुख्यालय में केंद्रित कर दिया गया, जिस पर पूरा नियंत्रण आयोग के आई टी सेल की प्रमुख सीमा खन्ना को दे दिया गया। विषय की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई कर रहा है।

इस लेख में हम एस आईआर की अनियमितताओं का उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि इस बारे में इसी संतंच में कई बार पहले भी मैं लिख चुका हूँ। अब तो स्वयं चुनाव आयोग ने भी उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में कई बातों को स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने यू टर्न लेते हुए कई निर्णय बदल भी दिए हैं।

इस आलेख में हम प्रमुख रूप से 2 अक्टूबर, 2026 के बाद ,ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए हो रहे आंदोलन और विशेष कर उसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका तथा उसके व्यवहार की चर्चा करेंगे। यह आंदोलन वैसे तो अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन “इंडिया ब्लॉक” भी कांग्रेस के नेतृत्व में कर रहा है, किंतु इसे सर्वाधिक जोर शोर से कांक्रोच जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व युवा कर रहे हैं।

कांक्रोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। शबाना आज़मी, विशाल दान्देलानी जैसी हस्तियों ने भी इसके समर्थन में भाग लिया।

वहीं पर, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा की। 3 अक्टूबर के बाद प्रलिदिन, विपक्षी दलों के गठबंधन “इंडिया ब्लॉक” द्वारा मार्च निकाले गए और प्रदर्शन किए गए। 6 अक्टूबर को मार्च में कपिल स्वब्ल, प्रशांत पृषण, योगेंद्र यादव और अरासका की अध्यक्ष और सबसे सक्रिय छात्र नेता नेहा बोरा ने भाग लिया। किसी को भी जंतर मंतर तक नहीं जाने दिया गया। पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर घरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और पूरे क्षेत्र में बी एन एस एस की धारा 163 (पुरानी आई पी सी की धारा 144) लगा रखी है।

प्रत्येक प्रदर्शन में राहुल गांधी, शिर्पका गांधी, नेहा बोरा और अनेक लोगों को सड़कों पर घसीट कर, बसों में भरकर हिरासत में लिया गया।

8 अक्टूबर को बैंगलोर में सी जे पी का प्रदर्शन था, जिसमें विख्यात, लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी और प्रसिद्ध फिल्म कलाकर प्रकाश राज ने भाग लिया। चूँकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।

जहां मुंबई पुलिस ने सी जे पी के प्रदर्शन को होने दिया, वहीं दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम करते हुए लोगों को जंतर मंतर तक नहीं जाने दिया गया।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन में सभी देशवासियों, विशेषकर युवाओं से दिल्ली पहुंचने की अपील की गई। ऐसी संभावना थी कि कांक्रोच जनता पार्टी द्वारा किए गए आह्वान के कारण हजारों-लाखों लोग दिल्ली पहुंच जायेंगे । इसी आशंका के चलते, 9 अक्टूबर को सरकार ने दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, दिल्ली आने वाली 235 ट्रेनों को रोक दिया और जंतर मंतर के 4 किलोमीटर के क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध करते हुए, विभिन्न अर्ध सैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आइटीबीपी, बीएएफए आदि के हजारों जवानों एवं अधिकारियों को कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बुलाकर दिल्ली में तैनात कर दिया। कई अर्ध सैनिक बलों को हवाई जहाज से लाया गया।

दिनांक 10 अक्टूबर को दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जंतर मंतर के आसपास भी नहीं फटक सके। पांच स्तरीय भारी बैरिकेडिंग की गई। ऑसू गैस, दंगा विरोधी बल की तैनाती के साथ ही सैकड़ों सी सी टीवी कैमरे लगा दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार अपने ही देशवासियों को शत्रु देश जैसा मान रही हो।

लोकतंत्र में, सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और वे जनता के लिए काम करती हैं। जिस प्रकार के दृश्य 9–10 अक्टूबर को दिल्ली में देखे गए, उनमें से कुछ का विवरण प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, क्योंकि मुख्य टी वी चैनल तो इस आंदोलन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे थे।

मेट्रो और अनेक ट्रेन निरस्त होने से लाखों लोगों को बहुत परेशानी हुई, विशेषकर उनको, जो इलाज हेतु अस्पताल नहीं पहुंच पाए। उल्लेखनीय है कि 1975 के घोषित आपातकाल में भी ट्रेनों को

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने

के लिए दिल्ली पुलिस के विरुद्ध

अवमानना याचिका दायर की गई है।

देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस के

अधिकारियों को अपने कुकृत्य के लिए

सजा मिलेगी? यदि पुलिस का ऐसा ही

व्यवहार रहा तो भारत और उत्तर कोरिया

जैसे देश में कोई अंतर नहीं रहेगा।

प्रधानमंत्री, स्वयं भारत को “मदर ऑफ

डेमोक्रेसी” कहते रहे हैं। अतः, पहल भी

उन्हें ही करनी पड़ेगी।

हिरासत में ले लिया। इसके वीडियो सबने देखे हैं। वहीं से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और पूरे दिन भर किसी को नहीं पता लगा कि उन्हें किस स्थान पर ले जाया गया। इसे अपहरण कहना गलत नहीं होगा।

दिल्ली में विभिन्न राज्यों से लगने वाली सीमाओं को भी सील कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार जैसे किसानों के आंदोलन के समय किया था। जब बड़े और भारी बैरिकेड तक को प्रदर्शनकारियों द्वारा हटाने की गठनाएँ हुईं, तो कोलों के द्वारा उन्हें मजबूती से जमीन में फाड़ दिया दिया गया।

सी जे पी की लीगल हेड और प्रमुख कार्यकर्ता रत्ना सिंह को अपने घर के बाहर ही, उनकी खुद की गाड़ी में कैद कर लिया गया। उन्होंने एक लाइव वीडियो में, जो सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ, यह दिखाया कि किस प्रकार कुछ दबंग लोग उनके पीछे और आगे लगातार बने रहे। एक प्रकाश से उन्हें ‘कार अरेस्ट’ कर लिया गया। वह स्थिति 7–8 घंटे तक बनी रही। फिर उन्हें अपने घर में जाने दिया गया किंतु उसके बाद भी उनके घर के आसपास कई व्यक्ति उन पर निगरानी करने के लिए बने रहे।

सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी को 10 अक्टूबर की प्रातः 7:00 बजे ही कुछ अज्ञात लोगों ने हिरासत में ले लिया। ध्रुव राठी ने तो इसे अपहरण बताया क्योंकि घर में घुसने वाले लोग पुलिस के थे या नहीं, यह भी नहीं पता लगा। उन्हें अगले दिन यानि 11 अक्टूबर को प्रातः 3 बजे छोड़ा गया। यदि उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया होता तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। स्पष्ट है, उनका कुछ लोगों ने अपहरण किया ताकि वह दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल न हो सके ।

इस प्रदर्शन के दौरान युवा लड़कों और लड़कियों के साथ अमानुषािक तत्वों ने बहुत दुर्व्यवहार किया। महिलाओं के कपडे तक फाड़ दिए। लड़कियां चीखती-चिल्लाती रहीं लेकिन पुलिस केवल देखती रही। ऐसा लगा कि उन्हें पुलिस का इशारा प्राप्त है और वे निश्चित थे कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी।

प्रेस रिपोर्ट्स को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्टरों के साथ भी बरतमीजी करके उन्हें हिरासत में लिया गया।

एक लड़का और एक लड़की 11 अक्टूबर को बैरिकेड के पास पोस्टर लेकर खड़े थे। उन्हें भी थोड़ी देर में पुलिस उठाकर ले गई।

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि पुलिस दमन और अत्याचार के जो दृश्य विभिन्न स्थानों पर देखने को मिले, वैसे किसी लोकतंत्र में तो संभव नहीं है। तानाशाही या सैन्य शासन में अवश्य हो सकते हैं। सरकार, शायद यह भूल गई कि 20 जुलाई को सोनम वांग्चुक की बलपूर्वक धरना स्थल से उठाने के बाद जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई, उसी का परिणाम यह हुआ कि धर्मैत्र प्रधान को इस्तीफा देना पडा था।

एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 7000 व्यक्तियों को केवल हिंसा होने की आशंका में गिरफ्तार कर लिया गया। वास्तविकता तो यह है कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल में भी जो कार्रवाई नहीं की गई, यह अघोषित आपातकाल में वर्तमान सरकार ने की है। सौरव दास से एक बात सीधे कही कि सरकार के द्वारा लोगों को जितना डरया जाएगा, उतना ही उनके मन से डर निकल जाएगा। फिलहाल, तो ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है ।

पुलिस के यह सोचना होगा कि वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है वह संविधान सम्मत नहीं है। पुलिस सत्ताधारी दल की नौकर नहीं है अपितु उसका काम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी, उसका एक प्रमाण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को रविवार 11 अक्टूबर को विशेष सुनवाई करनी पड़ी। न्यायालय ने आदेश दिए कि दिल्ली से सभी बैरिकेड हटाए जाएं, सारे मेट्रो स्टेशन खोले जाएं।

जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि ज्ञानेश कुमार का बने रहना सरकार के लिए कितना आवश्यक है? सरकार ने शायद युवाओं की शक्ति को ठीक तरह नहीं आंका है।

अब भी समय है कि सरकार युवाओं की शक्ति को पहचाने। विरोध प्रदर्शन, पूरे देश में उग्र रूप ले, उसके पहले ही सरकार को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए दिल्ली पुलिस के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है। देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अपने कुकृत्य के लिए सजा मिलेगी? यदि पुलिस का ऐसा ही व्यवहार रहा तो भारत और उत्तर कोरिया जैसे देश में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री, स्वयं भारत को “मदर ऑफ डेमोक्रेसी” कहते रहे हैं। अतः, पहल भी उन्हें ही करनी पड़ेगी।

–**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



पूर्णिमा जैमिनी

आई-स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश की युवा प्रतिभा में आत्मनिर्भरता की गूँज – स्टार्टअप्स दे रहे 50 हजार रोजगार, 2,600 महिला उद्यमी नेतृत्व में 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश

भजनलाल सरकार के दूरदर्शी कदमों से राज्य की युवा शक्ति को नई दिशा मिली है। युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानन्द की 163वीं जयन्ती पर गत 12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को राजस्थान युवा नीति – 2026 का उपहार दिया। इसमें और विकसित राजस्थान 2047 संकल्प में युवाओं को विकास और

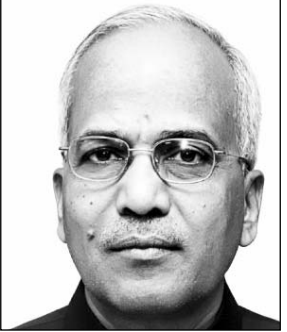
विश्वास का केंद्र बिन्दु माना गया है। गत लगभग 3 साल में युवाओं ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और परिवार के मुखिया के रूप में उनके द्वारा निभाये गये दायित्वों का सक्रियता से साथ दिया, अनुसरण किया और राज्य के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति का जब भी आव्हान किया, युवा ने आगे बढ़कर

सक्रिय समर्थन दिया, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान हो या हरियाली राजस्थान जैसे कार्यक्रम में जनभागीदारी निभानी हो या जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प हो।

हाल ही में सम्पन्न नगर निकाय चुनावों में युवा ने मतदान और इसके नतीजों के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पौने 3 साल के कार्यकाल को अपार समर्थन व्यक्त किया है। भजनलाल शर्मा के प्रति युवाओं का यह समर्थन एकाएक नहीं आया, यह उस भरोसे से आया है जो युवा खो चुके थे, शासन में भरोसा, व्यवस्था में भरोसा और अपने आप पर भरोसा। गत सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक पेपरलीक, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासे से युवा को लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। भजनलाल शर्मा ने उस भरोसे को जगाया है। यह भरोसा जगा है, सही निष्ठा मिली है। युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानन्द की 163वीं जयन्ती पर गत 12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को राजस्थान युवा नीति – 2026 का उपहार दिया। इसमें और विकसित राजस्थान 2047 संकल्प में युवाओं को विकास और

विश्वास का केंद्र बिन्दु माना गया है। गत लगभग 3 साल में युवाओं ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और परिवार के मुखिया के रूप में उनके द्वारा निभाये गये दायित्वों का सक्रियता से साथ दिया, अनुसरण किया और राज्य के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति का जब भी आव्हान किया, युवा ने आगे बढ़कर

यमुना की धारा से शेखावाटी का नया सवेरा



प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल

शेखावाटी के लिए यमुना जल का आमनन केवल एक जल परियोजना मात्र नहीं है। यह उस क्षेत्र के लिए विकास की नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला महत्वपूर्ण अवसर है, जिसने सीमित वर्षा, कठोर जलवायु, झुंडून् और चूरू की धरती ने अपाव

देश को सैनिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और उद्योगपतियों की असाधारण पीढ़ियां दी हैं। सीकर, झुंडून् और चूरू की धरती ने अपाव में भी उपलब्धि का इतिहास रचा है; अब यदि उस स्थानीय-सुरक्षा का आधार मिलता है तो उसकी मानवीय क्षमता को विकास का नया प्राकृतिक आधार मिल सकता है। 29 जून 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन संबंधी समझौते के बाद यह संभावना और ठोस हुई है। समझौते के अनुसार जुलाई से अक्टूबर के दौरान लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी तीन भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान पहुंचाया जाना है।

यमुना जल की कहानी 2026 से शुरू नहीं होती। 12 मई 1994 को ऊपरी यमुना बेसिन के उपयोग योग्य सतही जल के बंटवारे को लेकर राजस्थान सहित संबंधित राज्यों के बीच समझौता हुआ था। केंद्र सरकार के अनुसार उस व्यवस्था में राजस्थान का हिस्सा 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर () निर्धारित किया गया था, जबकि तजेवाला हेड पर जुलाई से अक्टूबर के दौरान राजस्थान के 1,917 क्यूसेक

महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष पेयजल है। सरकारी समझौते के अनुसार सीकर, चूरू और झुंडून् सहित राजस्थान के संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिस क्षेत्र में

हिस्से को उपयोग में लाने के लिए भूमिगत जल-परिवहन प्रणाली की दिशा में बाद में पहल की गई।

वर्ष 2017 में राजस्थान ने ताजेवाला से अपने हिस्से के पानी को भूमिगत प्रणाली के माध्यम से लाने के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यात रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की। फरवरी 2018 में डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिली और ऊपरी यमुना समीक्षा समिति ने भी राजस्थान को इस दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी। फरवरी 2024 में राजस्थान और हरियाणा ने संयुक्त रूप से डीपीआर तैयार करने पर सहमति बनाई। अब जून 2026 का निर्माण एवं क्रियान्वयन समझौता इस लंबी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।

लगभग 580 एमसीएम सुने में भले ही एक तकनीकी आंकड़ा लगने, लेकिन शेखावाटी जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए यह जल की एक बड़ी विकास-क्षमता का प्रतीक है। 2026 के समझौते में जुलाई से अक्टूबर के दौरान लगभग 580 एमसीएम पानी

राजस्थान पहुंचाने की व्यवस्था है। तीन भूमिगत पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से अधिक बताया गया है। यह व्यवस्था राजस्थान को 1994 में निर्धारित यमुना जल के अपने हिस्से का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस परियोजना की कल्पना में हथिनीकुंड बैराज से पानी लेकर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जुलाई 2026 में भी स्पष्ट किया गया कि हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा पानी राजस्थान लाया जाएगा और सीकर, चूरू, झुंडून् तथा आसपास के शेखावाटी क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।

यमुना जल परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष पेयजल है। सरकारी समझौते के अनुसार सीकर, चूरू और झुंडून् सहित राजस्थान के संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिस क्षेत्र में

नहीं हो पाता। प्रदेश में आई-स्टार्ट राजस्थानके अंतर्गत 4,623 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं और नवोदित उद्यमियों के 1,062 स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है।

युवा शक्ति की ऊर्जा से विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में भजनलाल सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख 93 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और निजी क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं। भजनलाल सरकार ने इन पौने 3 वर्षों में न केवल रोजगार के द्वार खोले हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि उन द्वारों से केवल योग्य और मेहनती युवा ही प्रवेश करें। सरकार ने नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह की जड़ पर प्रहार किया है। सरकार गउन के बाद विशेष जांच दल गठित किया गया। अब तक 138 एफआईआर दर्ज कर 569 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में 410 परीक्षाएं बिना किसी लीक या बाधा के सफलतापूर्वक आयोजित की गईं एसआई पेपर लीक मामले में 67 तत्कालीन उप निरीक्षकों (61 ट्रेनी 6 चयनित) सहित कुल 132 लोगों की गिरफ्तारी है कि उन द्वारा देने वाली के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है। परीक्षाओं की गोपनीयता और शुचिता बनाए रखने के लिए फूलप्रूफ व्यवस्थाएं की गईं। परिणाम यह हुआ कि ये अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक या गड़बड़ी के पूरी सुरुक्षा के साथ संपन्न कराई गईं, युवाओं का शिक्षा, परीक्षा,

संरकार से हुआ मोह भंग विश्वास में बदला है, अब योग्यता को पुरस्कार मिल रहा है। योग्य युवा नौकरी लग रहा है तो प्रशासन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। भजनलाल सरकार ने अपने शुरूआती काल में ही इस भ्रष्ट दीमक का जड़ मूल से सफाया कर नीतिगत स्पष्टता और दृढ़ इच्छाशक्ति का एक नया मानक स्थापित किया है। जहाँ पिछली सरकार के समय भर्तियां अटकती और भटकती थीं, वहीं भजनलाल सरकार की पारदर्शी नीति का ही सुखद परिणाम है कि मात्र ढाई वर्ष में 1 लाख 93000 युवाओं को सरकारी नियुक्तियां देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वर्तमान में रा्य सरकार द्वारा 1.22 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। राजस्थान का यह कायाकल्प केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि एक युवा केंद्रित युग का सूत्रपात है। पौने 3 वर्षों के कार्यकाल में नीति और सुशासन की क्रांतिकारी उपलब्धियां क्यों हासिल हुईं, यह बढ़ा सवाल है। उत्तर है- यह एक ऐसी सरकार है जो युवाओं की भाषा समझती है और उनके सघर्षों का सम्मान करती है। आज प्रदेश में एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी, अटल इनेवेशन स्टूडियो और लर्न-अर्न-प्रोग्रेस जैसे प्रोग्राम युवाओं के लिए भविष्य की राहें खोल रहे हैं।

R-CAT के जयपुर सेंटर के अतिरिक्त राज्य के प्रमुख संभागीय मुख्यालयों उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर आदि में इसके हब-एंड-स्पोक मॉडल आधारित केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जयपुर स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विश्वी रूप से विदेशी भाषा सीखने और इसके माध्यम से युवा

जलाशय का शिलान्यास किया और इसे शेखावाटी में यमुना जल लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार के अनुसार लगभग 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की यमुना जल परियोजना के अंतर्गत तीन पाइपलाइनों के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से सीकर, चूरू, झुंडून् और आसपास के क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाने की योजना है।

किमान से कृषि-उद्यमी तक यमुना जल का प्रभाव तभी व्यापक आर्थिक शक्ति में बदलेगा जब कृषि को केवल खेत में फसल पैदा करने तक सीमित न रखा जाए। उत्पादन के साथ संटाइण, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को जोड़ा जाए तो किसान मूल्य-श्रृंखला के अधिक बड़े हिस्से का भागीदार बन सकता है। इससे गांवों में कृषि आधारित छोटे और मध्यम उद्योग विकसित होने की संभावना बढ़ेगी और कृषि आय के नए रास्ते खुलेंगे। शेखावाटी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना का पानी आने का अर्थ यह नहीं कि शेखावाटी के पास असंमित पानी उपलब्ध हो जाएगा। औद्योगिक विकास में जल पुनर्चक्रण, अपशिष्ट जल उपचार, उपचारित पानी का पुनः उपयोग और जल ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को अनिवार्य महत्व देना होगा। भविष्य का उद्योग वही होगा जो कम पानी में अधिक आर्थिक मूल्य पैदा करे।

शेखावाटी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति है। जल उपलब्धता से कृषि, उद्योग, प्रसंस्करण, पशुपालन और सेवाओं में गतिविधियां बढ़ती हैं तो युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कृषि-तकनीक, ड्रोन आधारित खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए कोशल की मांग पैदा हो सकती है। इससे शेखावाटी का युवा रोजगार खोजने के साथ रोजगार देने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। जल-सुरक्षा का शिक्षा से संबंध प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता

को वैश्विक रोजगार कौशल के लिए तैयार करने की संकल्पना को साकार करता है।

जयपुर में महिलाओं के लिए और जोधपुर में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, एडवांस्ड स्किल यूनिवर्सिटी, जयपुर और एडवांस्ड ईवी मोबिलिटी लैब, जयपुर भी युवा को कौशल और रोजगार से जोड़ रहे हैं।

सामान्य कौशल विकास केंद्रों की बात करें तो राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के अंतर्गत पूरे राज्य के सभी जिलों में लगभग 87 से अधिक सक्रिय केंद्र संचालित हैं।

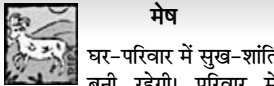
स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना यह दर्शाती है कि सरकार युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को उसकी मूल भावना में लागू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई मौकों पर दोहराया है कि जैसे नवाचार केवल एक मंच नहीं बल्कि हमारे युवाओं को ग्लोबल लीडर्स बनाने का लॉन्च पैड है। युवा शक्ति को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके राज्य की प्रगति में योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह आ न एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार की निर्णायक नीतियों और युवाओं की संकल्पित ऊर्जा के अद्भुत संयोजन से ग्ी राजस्थान की वीर भूमि पर युवाओं की अदम्य सामर्थ्य शक्ति से ही प्रदेश की उज्ज्वल निर्यात लिखी जाएगी।

–**पूर्णिमा जैमिनी,**
यंग मीडिया सहायक,
डीआईपीआर

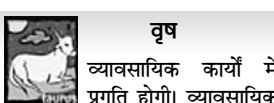
है। जब परिवारों का समय और संसाधन मूलभूत जल आवश्यकताओं पर कम खर्च होते हैं तो अधिक की शिक्षा और कौशल विकास के अवधि ध्यान देना संभव होता है। शेखावाटी पहले से शिक्षा के प्रति गहरी आकांक्षा वाला क्षेत्र है; जल-सुरक्षा के साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ना क्षेत्र की मानव पूंजी को और मजबूत करेगा।

शेखावाटी की हवेलियां, भित्तिचित्र और स्थापत्य राजस्थान की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत हैं। राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 को बताया कि झुंडून्, चूरू और सीकर में 660 से अधिक हवेलियों को शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर संरक्षित किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार में वृद्धि की संभावना भी जोड़ी है। जल, स्वच्छता, कनेक्टिविटी और विरासत संरक्षण के साथ यह क्षेत्र संस्कृतिक पर्यटन का और मजबूत केंद्र बनेगा। पानी मिलने के बाद गांवों का भविष्य केवल खेती तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं होगी। कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, छोटे उद्योग, डिजिटल सेवाएं, कौशल केंद्र और ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से गांव स्थानीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हो सकेंगे। इसके लिए जल के साथ सड़क, बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग और शिक्षा जैसी सुविधाओं को एकीकृत दृष्टि से विकसित करना होगा। जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार और आजीविका के अवसर नहीं होते, वहां युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। जल-सुरक्षा अकेले पलायन नहीं रोक सकती, लेकिन यदि उसके साथ कृषि, उद्योग, कौशल और उद्यमिता का विस्तार होता है तो स्थानीय रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। इस अर्थ में यमुना जल शेखावाटी में रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा।

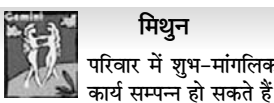
- **प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल**
कुलगुरु, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर



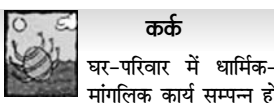
मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



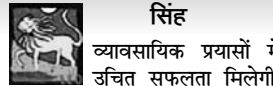
वृष
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।



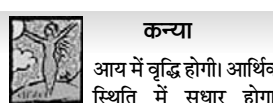
मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



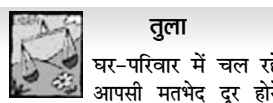
कर्क
घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।



कन्या
आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



तुला
घर-परिवार में चल रहे कार्यों में सुधार हो रहे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बने लेंगे